

वनमण्डलाधिकारी,
(सामान्य) वन मंडल,
जबलपुर, मध्यप्रदेश।

विषय:— जबलपुर जिले के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम के तहत सरस्वती घाट से भेड़ाघाट तक पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.09 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. शहरी विकास कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:— मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर का पत्र क्रमांक/मा0चि0/3868 दिनांक 09.07.2020

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार 01 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) amount of Rs. 56,340/- is to be paid for the 0.09 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- User agency shall restrict the No felling of trees shall be done.
- 5- प्रकरण में कोई वृक्ष नहीं काटे जाना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना रोपण अथवा 100 वृक्षों का रोपण किया जाना होता है। अतः प्रकरण में 100 वृक्षों की राशि 2000/- प्रति वृक्ष की दर से राशि रु. 2,00,000/- कैम्पा मद में जमा कराई जावे।
- 6- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

- 7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.
- 8- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 9- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 10- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 11- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 12- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 13- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 14- No work shall be done during night.
- 15- The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

उपरोक्तानुसार एन.पी.व्ही. की राशि रु. 56,340/- एवं 100 वृक्षों की राशि रु. 2,00,000/- आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। साथ ही वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर, जबलपुर का प्रमाण पत्र प्राप्त करे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है, तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने/क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।


(सुनील अग्रवाल)

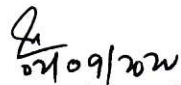
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 02/09/2020

पृ. क्रमांक/एफ-5/959/2020/10-11/2901
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
- 2- प्रोजेक्ट मैनेजर, मध्यप्रदेश शहरी विकास कम्पनी लिमिटेड, पी.आई.यू., 737 अग्रवाल कॉलोनी, जबलपुर, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)
मध्य प्रदेश, भोपाल